Prone Area Programme of Government of India. The estimated cost of this project is Rs. 154 crores. The District administration has already sent a proposal to the Government of Tamil Nadu and the same has been forwarded to the Government of India for its approval.

Keeping in view this drought situation, which is prevailing in Dharmapuri District, I urge upon the Government, through this august House, for an early clearance of the above said project under the Drought Prone Area Programme and to enable the District administration, Dharmapuri, Tamil Nadu, to have 515 new watersheds at an estimated cost of Rs. 154 crores.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now we will take up the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2003.

THE CONSTITUTION (SCHEDULED TRIBES) ORDER (AMENDMENT) BILL, 2003

गृह राज्य मंत्री (**श्री स्वामी चिन्मयानन्द**): माननीय उपसभापति महोदया, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं

> "कि असम राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची को उपातरित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

महोदया, इस विधेयक में ज्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है क्योंकि यह एक समझौते पर आधारित है। एक समझौता बोडो जनजातियों को स्वायत्त शासित परिषद देने के लिए 10 फरवरी, 2003 को किया गया था और उससे संबंधित छठी अनुसूची में संशोधन भी किया गया था। वह संशोधन भी माननीय सदन द्वारा पारित किया जा चुका है। केवल बोडो जनजातियों को वहां इस विधेयक के लागू होने के बाद जनजाति होने का जो अधिकार है वह समाप्त हो जाता है इसलिए यह अधिकार कायम रखने के लिए यह विधेयक लाया गया है। इस पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। अगर माननीय सदन चाहे तो इस पर चर्चा कर सकता है वैसे इसकी कोई आवश्यकता हमें महसूस नहीं होती। मैं अनुरोध करुंगा कि इसे पारित किया जाए।

The question was proposed.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, I have three names. Shrimati Vanga Geetha is absent. Shri Urkhao Gwra Brahma.

श्री उर्खाव गोरा ब्रहा (असम):उपसभापति महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया है। support the Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2003. मैं इसका समर्थन करता हूं। मैं भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि बोडो जनजातियों के बारे में, जो उनकी समस्याओं को लेकर एक समझौता हुआ था, उसको वास्तविक रूप से इम्पलीमेंट करने के लिए, यह बिल लाया गया है। मेरे पास इसके बारे में कहने के लिए ज्यादा बातें नहीं हैं। इस बार बोडो जनजाति को जनजाति मर्ज्यादा देने के साथ-साथ जो बोडो लैंड टेरीटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट स्वायत्त शासन बनाया गया है, इस स्वायत्त शासन के अंतर्गत जो जनजाति रहित है, उन लोगों के अधिकार सुरक्षित रखने के लिए यह बिल लाया गया है। मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूं। अमस में जनजाति के दो भाग हैं। एक है जो पहाड़ी इलाके में लोग रहते हैं एन.सी. हिल्स एंड करबी अंगलोंग, उन लोगों को हिल्स ट्राइब्स कहा जाता है और प्लेन्स एरिया मे जो रहते हैं उन लोगों को प्लेन्स ट्राइब्स कहा जाता है। बोडो लोगों को स्वायत्त शासन देने के पहले बोडो जनजातियों को प्लेन्स ट्राइब्स के नाम से जाना जाता था, उन लोगों की मर्ज्यादा प्लेन्स ट्राइब्स था, लेकिन बोडो लैंड टेरीटोरियल आटोनामस बनने जा रहे हैं, इसके बाद में एक सवाल आया है कि जो लोग आसाम मे रहते हैं, जो लोग बोडोलैंड आटोनामस टेरीटोरियल डिस्ट्रिक्ट के बाहर रहेंगे, उन लोगों का शैड्यूल्ड ट्राइब्स स्टेट्स क्या होगा? इसमें संविधान की समस्या आ गई है। इसको देखकर सरकार द्वारा बोडो लैंड टेरीटोरियल आटोनामस डिस्ट्रिक्ट के बाहर में रहने वाले बोडो लोगों की जनजाति मर्ज्यादा इसको कायम रखने के लिए यह बिल लाया गया है। लेकिन मेरे हिसाब से एक छोटी सी गलती है जिसे आप करने जा रहे हैं, इसमें एक कमी रह गई है जिसके बारे में मैं कहना चाहता हूं। आसाम में जो शैड्यूल ट्राइब्स आर्डर है पार्ट -2, आईटम-1 में आटोनामस डिस्ट्रिक्ट आफ करबी अंगलांग एन.सी.हिल्स है। इन दोनों आटोनमस डिस्ट्रिक्ट में जो ट्राइब्स रहते हैं, उन लोगों को स्पेसिफाई किया गया है। आईटम-2 में आसाम की प्लेन्स एरिया में जिस जनजाति के लोग रहते हैं, उन लोगों के नाम को स्पेसिफाई किया गया है। जो स्वायत्त शासन सिक्सथ शैडयूल के अंदर में बनाया गया है, यह स्वायत्त शासन जनजाति के लोगों के लिए बनाया जाता है। हमारा संविधान ऐसा ही कहता है। इसमें एक डिसक्रिमिनेश, इनजस्टिस होने जा रहा है कि टेरिटोरियल बोडो लैंड बनाने के बाद भी इस बोडो लैंड इलाके में कौन-कौन ट्राइबल, कौन-कौन जनजाति रहेगी, इसका नाम अलग से नहीं बनाया गया है। अगर इसको अलग से नहीं बनाया जायेगा तो किसी भी स्वायत्त शासन के जनजाति के लोग बोडो लैंड इलाके में आकर रहेंगे। यहां के राजनैतिक अधिकार, जमीन के अधिकार, सब फंडामेंटल कांस्टीट्यूशनल अधिकार उनको मिलेंगे। इलेक्शन में कंटेस्ट करने का अधिकार मिलेगा, इसमें समस्या आ सकती है और बोडो लैंड टेरिटोरियल आटोनामस डिस्ट्रिक्ट में जो ट्राइबल लोग रहते हैं, उन लोगों के अधिकार सुरक्षित कैसे रखे जायेंगे, इसका सवाल आ सकता है। इसीलिए मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि जैसे करबी आगलांग के लिए, जनजाति के लोगों की आपने लिस्ट बनाई है, एन.सी.हिल्स के लिये जनजाति के लोगों की लिस्ट बनाई है, उसी तरह से बोडोलैंड टेरिटोरियल आटोनामस डिस्ट्रिक्ट के लिए भी अलग से जनजाति के लोगों की

लिस्ट बनाई जाए। यहां पर तीन जनजातियां रहती हैं । Boro, Boro Kachari, Mech and Rabha इन तीन जनजातियों को इन बोडोलैंड आटोनामस डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट में शामिल किया जाये। मैं इसका अनुरोध करता हूं। जब Bodoland Territorial Autonomous District का बिल इस सदन में पारित हुआ था, उस समय मुझे बोलने को नहीं मिला था। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो एनडीए की सरकार है, उन्होंने बोडो समस्या को समझा और इसके समाधान के लिए जो रास्ता उन्होंने निकाला है, उसकी वजह से बोडो इलाके में शांति की प्रक्रिया शुरू हुई है। इसके लिए मैं एनडीए सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि सचमुच में बोडो जनजातियों की समस्या को समझने में एनडीए सरकार सफल हुई है और इसकी वजह से आज BTAD बनने जा रहा है। मैं विपक्ष के सभी सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, किन्तू वे लोग अभी सदन में नहीं हैं, कि असम में जो कांग्रेस सरकार है, संघ कांग्रेस सरकार ने इस प्रक्रिया में समर्थन किया और सभी सदस्यों ने लोक सभा में इसे पारित करने के समय समर्थन किया, इसकी वजह से बीटीसी का बिल पास हो पाया। लेकिन मुझे एक खेद है कि जो समझौता हुआ था, इसमें तीन प्रमुख मुद्दे रखे गए थे। एक था, बोडोलैंड टेरीटोरियल आटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बनाना, 6th शैड्यूल्ड में, दूसरा, बोडो भाषा को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची के अंदर लाना है, अंतर्युक्त करना है और तीसरा, Karbi Anglong and North Cachar Hills में रहने वाले बोडो लोगों को जनजाति का दर्जा देना है । BTC तो बनने जा रहा है और मुझे खुशी है कि एनडीए कीसरकार ने, इसकी केबीनेट ने बोडो भाषा को आठवीं अनुसूची में अंतर्युक्त करने का सिद्धांत लिया है, लोक सभा में यह इंट्रोड्यूज हो भी चुका है। मैं आशा करता हूं कि राज्य सभा में भी यह बिल इंट्रोड्यूज होगा। लेकिन जो बोडो जनजाति हैं, Karbi Anglong and North Cachar Hills में जो रहते हैं, उन लोगों को जनजाति में लाने की जो बात समझौते में की गयी थी, इसके बारे में कोई बिल नहीं लाया गया है। मैं अनुरोध करुंगा कि गवर्नमेंट का जो कमिटमेंट है, समझौते के द्वारा जो कमिटमेंट किया गया, जो एक नेशनल कमिटमेंट बन गया, इस नेशनल कमिटमेंट को रुपायण करना चाहिए। अगर इसको वास्तव में रुपायण नहीं किया जाएगा तो भविष्य में सरकार के जो कमिटमेंट होंगे, उन पर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता। मैंने अपनी बात सदन के सामने रखी है और मैं आशा करता हूं कि सरकार मेरी बात पर विचार करेगी। इस संबंध में मैंने अमैंडमेंट भी दिया है। मैं समय आने पर अमेंडमेंट मुव भी करुंगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri R. Kamaraj; he is not here. Shri Birabhadra Singh; do you intend to speak in Oriya?

SHRI BIRABHADRA SINGH (Orissa): Madam, I will speak in English as well as Oriya.

THE DEPUTY CHAIRMAN: You can speak in whichever language you feel comfortable.

SHRI BIRABHADRA SINGH: Thank you, Madam.

Madam, I rise to support this Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2003. I am very glad that the Bill will entitle the Bodos and the Bodo Kacharis of Assam, including the B.T.C. Areas District, and benefit them with the ST status. Madam, I will not confine myself to the issues of SCs and STs. After this amendment, some of .the tribes who are not included in the Scheduled Tribes list will be included. But my humble submission to the Central Government is, some other tribes who have migrated to the Bodoland territory from West Bengal, Orissa and Bihar should also be included in that list. I particularly know some tribes residing in Assam, which are not regarded as tribes. I mean to say, Madam, those who are tribals in Orissa, are regarded as non-tribals in Assam. The tribes of Assam are not there in West Bengal, but the tribes of West Bengal, Orissa and Bihar are residing in Assam. They are compelled to reside there. I know that the fore fathers of the hon. Chief Minister of Assam, Shri Prafulla Mahanta, were from the district to which I belong. But he was not a tribal. But those tribes, which are there in Assam, are not regarded as tribals. They had gone to Assam for their livelihood, to work in tea gardens, and in many ways, they were settled in Assam, but they are not regarded as tribals.

Madam, my point is, suppose I am a tribal, under the Constitution, I enjoy the benefits of a tribe in Orissa, West Bengal and Bihar also. But if my uncle or my son goes to Assam, and if due to circumstances he resides in Assam, he will not be regarded a tribal. This is the disparity which is seen in Assam, and also in the Andaman and Nicobar Islands. As a member of the SC & ST Welfare Committee, I raised this point once again, when we were on a tour to Assam and the Andaman and Nicobar Islands. It is not the question of it being a State subject. But when would a Constitutional Amendment be brought to this effect? A member of a Scheduled Tribe of. India is not from Bangladesh or Pakistan. He is a son of the soil. Under the Constitution, he enjoys the benefits of the tribe, but he is not regarded a tribe in Assam.

Therefore,. Madam, my humble submission is .that the Central Government should look into the matter. It must look into the case of tribals residing in Assam, especially the migrants, poor tribes, who were residing earlier in West Bengal, Bihar and Orissa, particularly, the Santhals, the Mundas, the Hose, the Kgals, the Bhumig, the Oraons and so many others. Madam, the sufferings they ate facing are beyond imagination. ऐसे आदिवासी

लोग तो आंखे होते हुए भी अंधे जैसे हैं। कान होते हुए भी देश की आवाज उनके कानों में नहीं जा पा रही है और मुंह होते हुए भी जैसे वे मूक होकर बैठे हैं। ऐसी हालत में असम में ज ट्राइबल लेबरर्स हैं, उनकी हालत क्या हो सकती है? इसलिए, I support this Bill. But I have an appeal to the Central Government. I do not think that with this Bill all our tribals will be included in the Tribes List. The Central Government should think seriously and bring an Amendment so that' our tribals in the neighbouring States will be benefited.

With these words, Madam. I support this Bill and hope that my appeal would be considered in due course. Madam, you have given me the time and opportunity to speak on this Bill and I am thankful to you for that. I conclude my speech with the hope that my appeal would be taken into consideration some day. Thank you, Madam.

SHRI INDRAMONI BORA (Assam): Madam Deputy Chairperson, I am grateful to you for giving me this opportunity. I stand here to support the Constitution (Scheduled Tribes) Order' (Amendment) Bill, 2003. Actually I was prepared for another two Bills, which were passed without discussion. I want to congratulate the Government of India, the Government of Assam and I consider that this Bill is a first step towards the establishment of peace in Assam as well as in the North-East. This is the first step. I want to appeal to the Home Minister present here that one problem is solved but there is another problem of terrorism in Assam. All those groups - ULFA, NDFB, TUJS - should also be invited for talks for an everlasting peace. This is my appeal to the hon. Minister. Madam, we have seen terrorism directly in Assam and in the North-Eastern States. These problems have not been properly taken care of since 1980. I do not want to blame anybody; for everything there is a time. I think, now the proper time has come for brining in peace to the North-East as well as to the country. We have seen developments towards peace in various .corners. Now. I again appeal to the hon. Minister to try and solve the problem of Assam. Why Bodos wanted a separate State first and then after negotiation they have come down to their own Council? The problem is that earlier they were under apprehension that their culture, language, etc.. will be grabbed by infiltrators who came across the border and they became conscious to have their own Government. Then afterwards, they were satisfied with the Council and I only pray to them. One of their leaders is here who took a lot of pain to bring the boys, who took to arms, to the negotiation table. I congratulate Shri U.G. Brahma, other Members of ABSU as an institution,

as they have recognised the democratic process and today we have seen this. There are some other problems. I have seen the Bill. The fund will be sent through the State Government. But, Madam, we have seen in Karbi Anglong and North-Cachar Hills, when the fund is channelized through the State Government, it never reaches the grass-roots. The leaders of Karbi Anglong and North-Cachar Hills have to go to whosoever is in power and beg for money. So, I appeal to the Minister to consider this point that funding should be direct to the Council because there will be Principal Secretary, I think, is competent enough to take care of the fund. I do not want to speak much. I again congratulate the Government of India, the Government of Assam, the Bodo leaders and ABSU leaders for trying their best to bring that area to a peaceful atmosphere. As my friend Shri Birabhadra Singh had said, there are different situations. Karbi people living in Karbi Anglong are Hill Tribes, but Karbi people living in areas other than Karbi Anglong within the State of Assam do not get that status. These problems are there. I appeal to the Government of India to look into all these problems of tribals and come for a settlement as early as possible. Otherwise, I am afraid, these people may also take recourse to some other measures which will not be palatable for the country as well as for the people of India. Thank you, Madam, for giving me this opportunity to speak a few words in this House although my name was not in the list.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, I have Dr. Arun Kumar Sarma. You please speak briefly because I want to finish it before 1 o'clock.

DR. ARUN KUMAR SARMA (Assam): Madam Deputy Chairperson, I thank you for giving me this opportunity to welcome this move of the Government for providing constitutional status to the B.T.C. areas, the autonomy, which was a long-pending demand of the Bodo people and after a long agitation and turmoil situation, peace has been restored. This is a very positive step for restoration of peace in the State of Assam. I congratulate the Government for bringing about this agreement and also finally for extending the constitutional status to the Bodo Territorial Council under the Sixth Schedule. I also appeal to the Government and also to the leaders of the Bodo movement to see that in the Bodo Territorial Council area, there are lot of non-Bodos whose interests should also be taken into consideration so that everybody feels happy and safeguarded in his own home area. Madam, through you, I want to bring one more issue along with Mr. Birabhadra Singh that the Joint Select Committee of the Parliament

had recommended for inclusion of various communities of Assam into Scheduled Tribes' list. These include Konch Rajbongshis, Ahom, Chutias, Moran, Motak and Tea Tribes. Inclusion of these communities is being recommended by the Joint Select Committee. It is in the process. I hope the Union Government will take very ardent steps to enlist all these communities of Assam which are entitled to be enlisted as Scheduled Tribes. So, a Bill may come up in the winter session of Parliament and with these words, once again, I thank you for having given me this opportunity. I also thank the Government and I support this Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Would you like to speak Shri Swami Chinmayanand?

श्री स्वामी चिन्मयानन्द: महोदया, मैंने अपने मित्रों को सुना है और उनके सुझावों पर सहानुभूतिपूर्क विचार भी किया जा सकता है, लेकिन यह विधेयक जिस समझौते से बंधा हुआ है, उस समझौते में जो भी प्रावधान किये गए हैं, उससे हम बाहर नहीं जा सकते। जहां तक ब्रह्म जी के सुझावप का सवाल है, उनको मैं कहना चाहता हूं कि कर्वी अंग लांग एंड एनसी हिल्ज बोडो जनजातियों को जनजाति का दर्जा देने पर सरकार विचार कर रही है और आगे चल कर उस पर काम हो सकता है। दूसरी जनजातियों को एस0टी0 का दर्जा देने के संबंध में माननीय सदस्यों ने जो सुझाव रखा है उसके बारे में मेरा निवेदन यह है कि एक अलग एस0सी0 एस0टी0 मंत्रालय उस पर विचार करता है और वही उस पर विचार करेगा। वह इस मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। इसलिए इस प्रकार का कोर्ड आश्वासन नहीं दिया जा सकता। इसके साथ डायरेक्ट फंडिंग की बात भी कही गई है। उसके संबंध में भी मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि संविधान हमें ऐसी कोई इजाजत नहीं देता कि हम ऐसी स्वायत्तशासी परिषद् को सीधे पैसा दे सकें।

जिन मित्रों ने नॉर्थ ईस्ट में या असम में दूसरे मिलिटेंट ग्रुप से बात करने के लिए कहा है तो माननीय उप प्रधानमंत्री जी ने सभी उग्रवादी संगठनों को, मिलिटैंट ग्रुप्स को एक तरह से खुला आश्वासन दिया है कि अगर वे हथियार डाल कर संविधान की सीमा में बात करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। माननीय प्रधानमंत्री जी पूर्वोत्तर राज्यों में शांति स्थापना के लिए अनेकों प्रयास कर रहे हैं और अनेकों तरह के कदम उठाए गए हैं। हम सभी उग्रवादी संगठनों से आग्रह करेंगे कि अगर वे शांति के इस प्रयास में और शांति के अभियान से जुड़ना चाहते हैं तो वे संविधान के प्रति अपना विश्वास व्यक्त करें और हथियार डाल कर अहिसक तरीके से बात करने के लिए आगे आएं तो उनका स्वागत हो सकता है।

इसी के साथ, महोदया, मैं आग्रह करुंगा कि इस विधेयक को पारित किया जाए।

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is :

That the Bill further to amend the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 to modify the list of Scheduled Tribes in the State of Assam, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up the clause-by-clause consideration of the Bill. There is an amendment to clause 2 by Shri Urkhao Gwra Brahma. Mr. Bramha, would you like to move.

SHRI URKHAO GWRA BRAHMA: Madam, I move:

That at page 1, *after* line 14, the following be *inserted* namely:-

"(iii) after the sub-part heading II, the following shall be inserted, namely: -

III. In the Bodoland Territorial Areas District the following Scheduled Tribes shall form the list of the bonafied Scheduled Tribes exclusively namely, -

(1) Boro, Borokchari

(2) Mech

(3) Rabha

The question was put and the amendment was negatived.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now. I shall put Clause 2 to vote.

Clause 2 was added to the Bill

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री स्वामी चिन्मयानन्द: माननीया, मैं आपसे अनुरोध करुंगा कि:

"विधेयक को पारित किया जाए"

The question was put and the motion was adopted.